

युवा शक्ति 2026: भारत के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी (संपादकीय / अग्रलेख)।

12 जनवरी को देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाता है। यह केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है— कि आज का युवा भारत किस दिशा में खड़ा है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प में उसकी भूमिका कितनी निर्णायक है। वर्ष 2026 में जब भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, तब “युवा शक्ति” केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) तभी वरदान बन सकता है, जब युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार और सही दिशा मिले। अन्यथा यही शक्ति सामाजिक असंतोष, बेरोज़गारी और हताशा का कारण भी बन सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपने युवाओं को अवसर दिए, वे आगे बढ़े; और जिन्होंने उपेक्षा की, वे पिछड़ गए।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था— “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।” आज यह वाक्य भारतीय युवाओं के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। डिजिटल युग में अवसरों की कमी नहीं है—स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र नए द्वार खोल रहे हैं। परंतु चुनौती यह है कि शिक्षा और कौशल प्रणाली अभी भी कई जगह बाज़ार की ज़रूरतों से मेल नहीं खा पा रही।

बेरोज़गारी और कौशल अंतर आज के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है। पढ़े-लिखे युवाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद उपयुक्त रोजगार का अभाव नीति-निर्माताओं के सामने गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। केवल डिग्री पर्याप्त नहीं; व्यावहारिक कौशल, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। इसी दिशा में सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे प्रयास किए गए हैं, पर ज़मीनी स्तर पर इनके प्रभाव को और मज़बूत करने की आवश्यकता है।

आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है—यदि उसे सही वातावरण मिले। स्वरोज़गार, स्टार्टअप और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सस्ते ऋण, मार्गदर्शन और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करनी होगी।

हालाँकि चुनौतियाँ केवल आर्थिक नहीं हैं। नशाखोरी, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया की लत और दिशाहीन सूचना भी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ अवसर देते हैं, वहीं भटकाव का खतरा भी बढ़ाते हैं। ऐसे में परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। युवाओं को आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना समय की मांग है।

लोकतंत्र की मजबूती में भी युवाओं की भूमिका निर्णायक है। मतदान, सामाजिक सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता से ही स्वस्थ लोकतंत्र संभव है। युवा यदि केवल दर्शक बने रहें, तो निर्णय कुछ ही हाथों में सिमट जाते हैं; लेकिन जब युवा भागीदारी करते हैं, तब व्यवस्था में ऊर्जा और पारदर्शिता आती है।

महिलाओं की भागीदारी के बिना युवा शक्ति अधूरी है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और नेतृत्व में युवतियों को समान अवसर देना राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है। विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होगी, जब युवा पुरुष और महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें।

अंततः, युवा शक्ति 2026 का अर्थ केवल संख्या नहीं, बल्कि चरित्र, क्षमता और चेतना है। सरकार को नीतियाँ बनानी होंगी, संस्थानों को उन्हें ईमानदारी से लागू करना होगा और समाज को युवाओं पर विश्वास करना होगा। वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह संकल्प लेना आवश्यक है कि भारत का युवा केवल अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी तैयार रहेगा। यही स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही भारत को विश्वगुरु बनने की ओर ले जाने वाली वास्तविक शक्ति।

WORLD NEWS | इजरायल में किया गया हाई अलर्ट,

इजरायल में किया गया हाई अलर्ट, क्या ईरान में हमले की तैयारी कर चुका अमेरिका? भारी तनाव

तेल अवीव: ईरान में दो हफ्ते से जारी विरोध प्रदर्शन और अमेरिका की अटक की धमकी ने इजरायल की चिंता बढ़ा दी है। ईरान में अमेरिकी दखल की संभावना को लेकर इजरायल में हाई अलर्ट किया गया है। इजरायल को डर है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की ओर से उसको निशाना बनाया जा सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को देखते हुए ईरान में भी सेना और रक्षा से जुड़े संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है।



ईरान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के उन बयानों की निंदा की है, जिनमें तेहरान में दखल की बात कही गई है। ईरान के मंत्रालय ने कहा कि ये बातें चीजों को खराब करने वाली और लोगों को गुमराह करने वाली हैं। इससे साफ होता है कि अमेरिका ईरानी जनता के प्रति दुश्मनी रखता है। हम किसी भी दखल का कड़ा जवाब देंगे।

ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बीते दो हफ्ते से प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश की मुद्रा रियाल आई गिरावट और आर्थिक परेशानियों के चलते शुरू हुए। ये प्रदर्शन अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों की ओर से हिंसा और तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

ईरान में दो सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या कम से कम 116 हो गई है। अमेरिका की एक मानवाधिकार संस्था ने यह जानकारी दी है। ईरान में इंटरनेट और फोन लाइन काट दी गई है।

ट्रंप ने फिर दिया बयान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान में जो हालात बने हुए हैं, उसमें उनका देश दखल दे सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है, 'ईरान स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका इसमें प्रदर्शनकारियों की हर आर्मी के निशाने पर होंगे। इसके बाद इजरायल में अलर्ट है।

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है, तो अमेरिका इस मामले में कूद जाएगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनका ईरान में सेना भेजने का मकसद नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान में ऐसी जगहों पर वार करेंगे, जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है, तो अमेरिका इस मामले में कूद जाएगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनका ईरान में सेना भेजने का मकसद नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान में ऐसी जगहों पर वार करेंगे, जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा।

WORLD NEWS | इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी,

इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी, क्या पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी को रोक पाएंगे भारत-इजरायल? बढ़ा तनाव

NEWS AGENCY

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीते साल नाटो स्टाइल का अहम रक्षा समझौता हुआ है। इसमें अब तुर्की के भी शामिल होने की संभावना है। इसे एक इस्लामिक नाटो की तरह देखा जा रहा है।



अंकारा: सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बीते साल स्ट्रेटेंजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) किया है। इस समझौते में तुर्की भी शामिल हो सकता है। तुर्की-पाकिस्तान-सऊदी अरब का ये गठबंधन बड़ा भूराजनीतिक घटनाक्रम है। इस समझौते में एक देश पर हमले को दोनों पर अटैक माना जाएगा। यह नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। अगर यह त्रिपक्षीय गुट बनता है तो सऊदी अरब की माली हैसियत, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और नाटो के दूसरा बड़े सैन्य योगदानकर्ता के तौर पर तुर्की का भूराजनीतिक दबदबा होगा।

यूरोशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन को

'इस्लामिक NATO' के विजन की तरफ कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह गठबंधन फाइनल होता है तो यह भारत, इजरायल, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत और इजरायल की साझेदारी इसके रास्ते में अहम बाधा बनेगी। दोनों देशों की मजबूत सैन्य और रक्षा साझेदारी है।

भारत-इजरायल संबंध तुर्की-पाकिस्तान-सऊदी के गुट के रूप में अगर इस्लामिक नाटो जैसा एक गठबंधन बनता है तो उसके सामने इजरायल और भारत की साझेदारी एक चुनौती बन सकती है। भारत ने 1996 में इजरायल के साथ औपचारिक रक्षा संबंध स्थापित किए।

इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी आई है। इजरायल खासतौर से हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर रहा है

भारत ने इजरायल से कई सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिनमें बराक नौसैनिक एंटी-मिसाइल रक्षा प्रणाली हासिल की है। भारत को इजरायली हार्प्री और मंडराने वाले हारोप किलर लोडिंग मिले हैं। इजरायल भारत के स्वदेशी AD सिस्टम का समर्थन कर रहा है, जिसमें एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली शामिल है। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी इजरायली हथियार मददगार रहे हैं।

इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी, क्या पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी को रोक पाएंगे भारत-इजरायल? बढ़ा तनाव

तुर्की क्या देख रहा है
सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ नाटो शैली के सैन्य गठबंधन में तुर्की ने शामिल होने का संकेत दिया है। तीनों देशों में हालिया दिनों में इस पर चर्चा हुई है और जल्दी ही इसको लेकर फाइनल एलान हो जाने की संभावना है। इसने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है।

सितंबर, 2025 में में सऊदी-पाक रक्षा समझौते की तर्ज पर बना यह संभावित गठबंधन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। भारत के लिए इसमें खासतौर से पाकिस्तान की भूमिका चिंता का विषय है। पाकिस्तान को तुर्की की सैन्य मदद और सऊदी अरब की वित्तीय सहायता किसी टकराव में बहुत मजबूत कर सकता है।

ग्रीनलैंड पर हमले में क्या सिर्फ कुछ घंटे बाकी? ट्रंप ने सेना प्रमुख को दे दिया आदेश, रूस-चीन का डर

वॉशिंगटन: ग्रीनलैंड पर अमेरिका का सैन्य हमला बहुत जल्द हो सकता है। यह आशंका जताई जा रही है क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पेशल फोर्स के प्रमुखों को ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बनाने को कहा है। ट्रंप ने कथित तौर पर अमेरिकी सेना के शीर्ष अफसरों से कहा है कि उनका ग्रीनलैंड में कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इस मामले में ज्यादा देरी ठीक नहीं है। ट्रंप को लगता है कि ग्रीनलैंड पर देर करने से चीन और रूस को वहां दखल का मौका मिल सकता है। ऐसे में अगले कुछ दिनों या घंटों में ही हमले की आशंका कई एक्सपर्ट ने जताई है।

यह रिपोर्ट ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा के पीछे अमेरिका की सुरक्षा का हवाला दिया है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा तो चीन या रूस यह कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वह ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं और इसके लिए सैन्य विकल्प खुला है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।

ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बनाने का आदेश डेली मेल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप जल्दी से जल्दी ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान चाहते हैं। ट्रंप हमले की योजना के लिए जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इससे सहमत नहीं हैं। दूसरी ओर राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिल ग्रीनलैंड पर कार्रवाई चाहते हैं।

रिपोर्ट में डिप्लोमैटिक केबल के हवाले से कहा गया है कि थरेलु राजनीतिक कारणों से ट्रंप एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं, जो बाद में समझौते की तरफ मुड़े। यूरोपीय अधिकारियों को डर है कि ट्रंप के लिए मिड-टर्म से पहले मौके खत्म हो रहा है, इसलिए वह जल्द ही ग्रीनलैंड में कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अभी सेना में इस पर एकराय नहीं है।

ट्रंप को चीन-रूस से खतरा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा करनी होगी क्योंकि उस पर रूस और चीन की नजर है। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए हमें उले अपने नियंत्रण में लेने की ज़रूरत है।

डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल और हालिया दिनों में कई बार कहा है कि ग्रीनलैंड का अमेरिका के नियंत्रण में होना उनके देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी ओर डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने कहा है कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं। डेनमार्क सरकार ने अमेरिका के सैन्य हमले की सूत को नाटो के खत्म हो जाने तक की धमकी दी है।

ग्रीनलैंड पर क्यों है अमेरिका की नजर
ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका और आर्कटिक के बीच है। यहां के लोग खुद अपना शासन चलाते हैं लेकिन विदेश नीति और सेना डेनमार्क के पास है। अपनी विशेष स्थिति (लोकेशन) की वजह से ग्रीनलैंड मिसाइल हमलों की स्थिति में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के लिए अहम है। जहाजों की निगरानी के लिए भी यह





महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Monday 12th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 257 , पृष्ठ 03



अजीत पवार ने 'लाडकी बहिन योजना' भुगतान तारीख पर स्पष्ट किया बयान, कांग्रेस की चुनाव आयोग में शिकायत

महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भत्ते की भुगतान तारीख पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने स्पष्ट किया कि ₹3,000 की किस्त विस्तृत रूप से संकटापूर्वक चुनाव आयोग के निर्णय पर निर्भर करेगी और आयोग के निर्देश के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। योजना को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने निवडणूक आयोग को शिकायत भी दर्ज करवा दी है।

कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मांग की है कि दिसंबर 2025 और

जनवरी 2026 की भुगतान किस्तें नगर निकाय चुनावों के बाद जारी की जाएं, ताकि चुनाव के दौरान इस योजना के भुगतान से मतदाताओं पर राजनीतिक प्रभाव न पड़े। कांग्रेस का तर्क है कि इसके साथ आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। अजीत पवार ने reaffirm किया है कि जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, यह योजना जारी रहेगी, लेकिन भुगतान तिथि आयोग की अनुमति पर निर्भर करेगी। पवार के बयान के बाद भी राजनीतिक बहस जारी है और विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

अहमदाबाद का नाम बदलें — उद्धव ठाकरे की अमित शाह को चुनौती



संवाददाता

छत्रपती संभाजीनगर में महापालिका चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती करने की चुनौती दी। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने जैसे बड़े फैसले भले ही लिए हों, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा उन पर गलत दावा करती है। इसलिए अगर भाजपा में वाकई हिम्मत है तो अमित शाह जिन्होंने अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व किया है, वह शहर का नाम कर्णावती कर दिखाएं, यह चुनौती उन्होंने शनिवार को सभा में दी।

ठाकरे ने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई

कोहली ने बताया POTM ट्रॉफी का असली रखवाला — "मैं भेजता हूँ माँ को"



भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद एक मजेदार खुलासा किया है। वडोदरा में खेले गए मैच में शानदार 93 रन की पारी खेलकर कोहली को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' (POTM) चुना गया, जिसे उन्होंने अपनी 45वीं POTM ट्रॉफी बताया।

ट्रॉफी मिलने पर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि उन्होंने कुल कितनी POTM ट्रॉफियाँ जीती हैं, तो कोहली ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका खुद को भी हिसाब नहीं है और वह हर ट्रॉफी अपनी गुरुग्राम में रहने वाली माँ के पास भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें यह सबसे ज़्यादा पसंद है। कोहली ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत उपलब्धियों की परवाह करने से ज़्यादा उनका ध्यान टीम की जीत पर रहता है और वह अपने पूरे करियर को एक सपने के साकार होने जैसा मानते हैं।

MAHARASHTRA NEWS | फडणवीस बोले: कुंभ मेळा "अकबर के पूर्वजों" से भी पहले की परंपरा

फडणवीस बोले: कुंभ मेळा "अकबर के पूर्वजों" से भी पहले की परंपरा, नाशिक विकास के साथ धर्म-संस्कृति की पहचान बनाए रखेगा

नाशिक | नाशिक महानगरपालिका चुनाव 2026 के प्रचार के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाशिक कुंभ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजय संकल्प सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नाशिक का कुंभ मेळा सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की प्राचीन पहचान है और यह कोई रोक नहीं सकता। फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मेळा "अकबर के बाप के बाप" से भी पहले से नाशिक में आयोजित होता आया है, जो इसकी ऐतिहासिक गहराई और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है।

उन्होंने 2015 के नाशिक कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए बताया कि कम समय के बावजूद उस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। उनका कहना था कि नाशिक कुंभ की परंपरा बेहद प्राचीन है और यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे किसी भी बाहरी शक्ति से रोका नहीं जा सकता।

पुणे-PCMC चुनाव: फडणवीस-अजित पवार आमने-सामने, महायुती में तल्लू माहौल

महाराष्ट्र में 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच राजनीतिक टकराव तेज़ होता जा रहा है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और एनसीपी के बीच नहीं है, बल्कि महायुती (BJP-Shiv Sena-NCP) के भीतरही तनाव का स्वरूप लेती दिख रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अब तक संयम बनाए रखा है, लेकिन अजित पवार का संयम ढल गया है और पवार के बयान चुनावी माहौल को और अधिक गरमा रहे हैं।

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड में महायुती के रूप में गठबंधन नहीं होगा और दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, जिससे स्थानीय सत्ता पर कब्जा करने को लेकर सियासी रण अधिक तीव्र होगा।

हाल ही में पिंपरी-चिंचवड में महापालिका चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार ने बीजेपी पर आरोप



मुख्यमंत्री ने नाशिक के आर्थिक व बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नाशिक का विकास केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर को लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। फडणवीस ने विमानतल विस्तार, नए रिंग रोड, नाशिक-पुणे तथा नाशिक-सोलापूर हाईवे जैसे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे नाशिक

की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस बीच, चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे नाशिक की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को समझे बिना ही राजनीति कर रहे हैं, और विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।



सेवरी रैली में नितेश राणे का ठाकरे बंधुओं पर तीखा हमला, 'जय श्रीराम' को लेकर चेतावनी

मुंबई महापालिका चुनाव (BMC Election 2026) के मद्देनजर सेवरी में आयोजित एक प्रचार रैली में भाजपा नेता नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने विरोधी पक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुत्व, मराठी माणूस और मुंबई की अस्मिता के मुद्दों पर ठाकरे बंधुओं की भूमिका संदिग्ध है और जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है।

राणे ने कहा कि यदि मतदाता 16 तारीख के बाद सतर्क नहीं रहेगा तो 'जय श्रीराम' कहना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिये महायुति गठबंधन को समर्थन देना आवश्यक

शिंदे-भाजपा की सत्तायात्रा पर कांग्रेस का तीखा हमला: हैदराबाद व ठाणे के 'दाढ़ी वालों' को एक सिक्के के दो पहलू बताया



महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनावों के बाद राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा की वर्तमान सत्तासंघ की राजनीतिक रणनीति पर तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि हैदराबाद का दाढ़ी वाला और ठाणे का दाढ़ी वाला "एक ही सिक्के के दो पहलू" हैं, जिससे उन्होंने सत्ताधारियों की कथित राजनीति को बर्खास्त किया है।

सपकाळ ने आरोप लगाया कि भाजपा और शिंदे-शिवसेना ने चुनावी रणनीति के तहत हर बार सत्ता के लिए विरोधी विचारधाराओं वाले दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसे उन्होंने खतरनाक और पाखंडी बताया। उन्होंने कहा कि अकोट में भाजपा ने और बीड़ में शिंदे-शिवसेना ने एमआईएम के

है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मराठी लोगों के मुद्दों का उपयोग केवल सत्ताधारी हितों के लिये किया जा रहा है, जबकि भाजपा और महायुति इस पहचान की रक्षा के लिये सबसे आगे हैं।

नितेश राणे ने बाळासाहेब ठाकरे के विचारों तथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी ने ठाकरे के सपनों को साकार किया है और मतदाताओं से महायुति के पक्ष में वोट देने का आग्रह किया। रैली में महायुति के उम्मीदवारों के लिये समर्थन की अपील भी की गई।

साथ गठबंधन कर वास्तव में अपनी सत्तास्थिति बचाने के लिए धार्मिक और जातीय विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया है।

सपकाळ ने कहा कि सत्ताधारी दलों की यह चाल मतदाताओं को भ्रमित करने वाली है क्योंकि प्रचार में लोग धार्मिक भावनाओं का उपयोग करते दिखते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए वे किसी भी राजनीतिक गठबंधन से आगे नहीं हटते। उन्होंने इसे "बोचरी राजनीति" कहा और जनता से इस खेल को पहचानने का आग्रह किया।

साथ ही उन्होंने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम वरिष्ठ नेता दि. बा. पाटील के नाम पर रखने की मांग भी दोहराई और भाजपा पर कोडगेपणा (निष्क्रियता) के आरोप लगाए। सपकाळ ने कहा कि आचारसंहिता समाप्त होने के बाद हवाई अड्डे का नामकरण तुरंत किया जाना चाहिए।

राजनीतिक पटल पर यह बयान कांग्रेस द्वारा सत्तापक्ष की नीतियों और चुनावी रणनीतियों पर चल रहे विवादों को और तेज कर रहा है, जिससे आगामी स्थानीय चुनावों में राजनीतिक दबाव और सतह पर आ गया है।



नंदिग्राम टाईम्स



तरोड़ा (बु.) में उद्धव ठाकरे शिवसेना की मशाल रैली, अपर्णा देशमुख के समर्थन में उमड़ा जनसमर्थन

नांदेड़। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से तरोड़ा (बु.) क्षेत्र में वाई क्रमांक 2 की उम्मीदवार अपर्णा गजानन देशमुख के समर्थन में भव्य मशाल रैली का आयोजन किया गया। सायंकाल के समय निकाली गई इस रैली ने पूरे क्षेत्र को रोशनी और उत्साह से भर दिया, जिससे वातावरण पूरी तरह जीवंत हो गया।

इस रैली में शिवसेना के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। क्षेत्र की जनता लंबे समय से उन्हीं पुराने चेहरों को देखकर असंतोष महसूस कर रही है और नए, कर्मठ नेतृत्व की तलाश में है। ऐसे समय में मशाल रैली ने तरोड़ा (बु.) में परिवर्तन का संदेश देते हुए लोगों में नया जोश और विश्वास पैदा किया।

रैली के पश्चात आयोजित जनसभा में भारी

संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता धोंडू पाटील ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव आम जनता के अधिकारों और निष्ठावान शिवसैनिकों के संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें निश्चित रूप से जनता की जीत होगी।

जिला प्रमुख भुजंग पाटील ने अपने भाषण में विरोधी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए अपर्णा देशमुख को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। महानगर प्रमुख प्रकाश मारावार ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जबकि उपजिला प्रमुख व्यंकोबा येडे ने सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली की आलोचना की। इस कार्यक्रम में तालुका प्रमुख सुनील कदम, बंडू देशमुख, गजानन देशमुख, नागनाथ माधापुरे सहित अनेक वरिष्ठ और निष्ठावान शिवसैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

प्रकाश आंबेडकर ने छत्रपती संभाजीनगर में भाजपा को न वोट देने का आग्रह किया



संवाददाता |

छत्रपती संभाजीनगर में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहाँ प्रकाश आंबेडकर ने एक रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट न देने की अपील की है। उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी का कार्यकाल “कंबरडॉ मोडलैंग” यानी जनता को निराश किया है और यह समय है कि लोग बदलाव की ओर देखें।

आंबेडकर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि सनातन हिंदुओं को भाजपा के समर्थन से परहेज करना चाहिए और मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने यह बयान छत्रपती

संभाजीनगर की जनता से सीधे संवाद के दौरान दिया, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों को स्थानीय चुनावी संदर्भ में जोड़ने की कोशिश की। इस अपील का मकसद स्पष्ट रूप से भाजपा के खिलाफ वोट बैंक को प्रभावित करना है, खासकर स्थानीय निकाय चुनावों के समीप आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। विपक्षी नेताओं द्वारा मोदी सरकार और भाजपा पर लगाए गए आरोपों ने क्षेत्र में चुनावी चर्चा को और उभारा है। इन बयानों के बाद आगामी चुनावों में मतदाताओं की प्रतिक्रिया और राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव पर नजर बनी हुई है।

ज्येष्ठ समाजवादी नेता गंगाधरराव पटणे का निधन, समाजवादी आंदोलन को अपूरणीय क्षति



नांदेड़/(संवाददाता)—जनता दल के पूर्व विधायक और वरिष्ठ समाजवादी नेता गंगाधरराव पटणे का गुरुवार को नांदेड़ में वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। पटणे 1998 से 2004 तक विधान परिषद के सदस्य रहे तथा 1974 से 1981 के दौरान बिलोली नगर परिषद के नगराध्यक्ष रहे। साने गुरुजी और महात्मा बसवेश्वर के विचारों से प्रेरित पटणे शिक्षा प्रेमी, पुस्तकालय आंदोलन के मजबूत स्तंभ और समाजवादी चिंतक के रूप में पहचाने जाते थे। उन्होंने देहदान का संकल्प लिया था, जिसके अनुसार उनका पार्थिव श्री गुरु गोविंद सिंहजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को सौंप दिया गया। उनके निधन से सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



NWMC ELECTION 2026 | नांदेड़ में भाजपा का ‘बोरिया-बिस्तर’ तय : सांसद रविंद्र चव्हाण

मोदी सरकार ने शहर को विकास से वंचित किया, महापालिका चुनाव में होगा सूफड़ा साफ,नांदेड़ में भाजपा का ‘बोरिया-बिस्तर’ तय : सांसद रविंद्र चव्हाण

नांदेड़, संवाददाता। : भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय नेतृत्व को मराठवाड़ा के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने से लेकर नांदेड़ के राजस्व आयुक्तालय तक, हर महत्वपूर्ण मुद्दे को भाजपा सरकार ने जानबूझकर लटकाकर रखा है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद नांदेड़ को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित किया गया है। इसी कारण आगामी महानगरपालिका चुनाव में नांदेड़ की जनता भाजपा का ‘बोरिया-बिस्तर’ बांधने का मन बना चुकी है, ऐसा विश्वास सांसद रविंद्र चव्हाण ने व्यक्त किया।

वे नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव के प्रचार अभियान के तहत प्रभाग क्रमांक 8 में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर श्याम दरक, हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर, राजेश पावड़े, फारूक अहमद, प्रशांत इंगोले सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।



सांसद चव्हाण ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के माध्यम से नांदेड़ को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला, जिससे शहर का कायाकल्प हुआ। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया गया, जिसका सीधा नुकसान नांदेड़ के विकास को

झेलना पड़ा। आज विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाले स्थानीय भाजपा नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन नांदेड़ की जनता अब इन झूठे वादों के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सभी जाति-धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। आने वाले पांच वर्षों में युवा नेतृत्व के माध्यम से शहर के विकास को नई दिशा दी जाएगी।

कांग्रेस-वंचित आघाड़ी के पास ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनमें विकास की प्रतिबद्धता और मजबूत जनसंपर्क है। इसलिए नांदेड़ के सुरक्षित और प्रगतिशील भविष्य के लिए महापालिका की सत्ता कांग्रेस-वंचित आघाड़ी को सौंपने की अपील उन्होंने मतदाताओं से की।

मराठवाड़ा के प्रति भाजपा में संवेदना का अभाव महायुति पर तीखा प्रहार करते हुए सांसद चव्हाण ने कहा कि नांदेड़ में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस—तीनों दल एक-दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। गठबंधन केवल नाम तक सीमित रह गया है, जबकि अंदरखाने एक-दूसरे की टांग खींचने का खेल चल रहा है। जनता को हल्के में लेने वाली इन पार्टियों को इस बार मतदाता उनका सही स्थान दिखाएंगे।

इस सभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस-वंचित आघाड़ी की जीत निश्चित है। सभा में प्रभाग क्रमांक 8 के नागरिकों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

विधायक के एलएक्यू के बाद भी हालात जस के तस; बिलोली में रैत माफियाओं का राज, प्रशासन की ‘मौन सहमति’?



घरकुल सपनों पर डाका है।

बिलोली (संवाददाता): बिलोली तहसील में अवैध रेत तस्करी का काला कारोबार एक बार फिर पूरे जोर-शोर से शुरू हो गया है। हालात ऐसे हैं कि माफिया पूरी ताकत में हैं, प्रशासन गहरी नींद में और कार्रवाई केवल कारागृहों तक सीमित नजर आ रही है। लोकतंत्र के मंदिर में आवाज़ उठते ही कुछ दिनों के लिए शांति छा जाती है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक गहमागहमी ठंडी पड़ती है, तस्करो को फिर से ‘हरी झंडी’ मिल जाती है। यही बन गया है कुख्यात ‘बिलोली पैटर्न’।

देगलूर-बिलोली के विधायक जितेश अंतापुरकर ने शीतकालीन अधिवेशन में तारांकित प्रश्न (एलएक्यू) के जरिए अवैध रेत परिवहन पर सीधा हमला बोला था। विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही उन्होंने उपविभागीय अधिकारी क्रांति डोंबे और तहसीलदार गजानन शिंदे की ‘आशीर्वादपूर्ण भूमिका’ का गंभीर आरोप लगाया था। इस बयान से प्रशासन में खलबली मच गई और करीब 15 से 20 दिनों तक रेत तस्करी पूरी तरह ठप रही। लेकिन अधिवेशन समाप्त होते ही राजनीतिक चर्चा भी धमी और तस्करी एक बार फिर पहले जैसी रफ्तार से शुरू हो गई। साफ है कि प्रश्न से तस्करी रुकती है, प्रशासन से नहीं।

नदी घाटों पर खुलेआम लूट हुंगुंदा, गंजांगव, येसगी, सगरोली और कोलगांव जैसे नदी घाटों से रोज रात 2 बजे से शाम 6 बजे तक हायवा ट्रक और सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। यह केवल रेत की चोरी नहीं, बल्कि नदियों के अस्तित्व पर हमला, पर्यावरण का विनाश, सरकारी राजस्व की लूट और गरीबों के

घरकुल लाभार्थियों का शोषण सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अवैध रूप से जमा की गई रेत को दौंगुने-तिगुने दाम पर घरकुल योजना के लाभार्थियों को बेचा जा रहा है। जिन्हें सरकार घर देने का संकल्प लेती है, उन्हीं पर माफिया रेत खरीदने की मजबूरी थोप रहे हैं। योजना सरकार की, लेकिन मुनाफ़ा दलालों का!

रेत तस्करी रोकने के लिए तहसील स्तर पर विशेष पथक तैनात किया गया है, लेकिन यह पथक न नदी में दिखता है, न घाट पर, न सड़कों पर—सिर्फ फाइलों और हाज़िरी रजिस्टर तक सीमित है। पथक ‘कागज़ी बाघ’ बन चुका है और तस्कर ‘सड़कों के शेर’।

स्थानीय नागरिकों का खुला आरोप है कि पथक के कुछ कर्मचारियों को ‘घर-पोच मलिका’ मिलता है, इसी वजह से कार्रवाई न के बराबर है। अब सवाल यह है कि क्या बिलोली में अवैध रेत तस्करी पर सच में लगाम लगेंगी? या फिर हर बार की तरह कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद माफिया फिर से बेखौफ़ राज करता रहेगा?



नागपुर MIHAN को Boeing-777 मेंटेनेंस की मंजूरी

नागपुर के MIHAN (Multi-modal International Cargo Hub and Airport at Nagpur) प्रोजेक्ट को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। अमेरिकी विमानन प्रशासन ने Boeing-777 जैसे बड़े विमान की रख-रखाव (Maintenance) सेवाओं के लिए MIHAN को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इससे नागपुर को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमान मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सेंटर के रूप में मान्यता मिलने जा रही है।

इस फैसले का असर सीधे नागपुर की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि बोइंग जैसे बड़े विमानों की सेवा के लिये विशेषज्ञ तकनीशियन,

इंजीनियरों व अन्य सुविधाओं की जरूरत होगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि MIHAN को मिली यह मंजूरी नागपुर को वैश्विक विमानन रख-रखाव हब की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत को इस तरह की सेवाएं विदेशों पर निर्भर रहने की बजाय देश के भीतर ही उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बचत भी संभव हो सकेगी। MIHAN के विकास से नागपुर का वैश्विक लॉजिस्टिक्स और एयरोस्पेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थान मजबूत होगा, जो आगामी वर्षों में और निवेश आकर्षित कर सकता है।

शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना विधायक कोहलीकर को पड़ा महंगा, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने तलब किया मुंबई



नांदेड़ (संवाददाता) : नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव के दौरान शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाने के शिवसैनिक और नागरिक उपस्थित थे। होली, मन्यार गली, विणकर कॉलोनी और चौपाला क्षेत्र के मतदाता बड़ी संख्या में सभा में शामिल हुए। विधायक हेमंत पाटील ने आह्वान किया कि शिवसेना की भगवा लहर को नांदेड़ महानगरपालिका तक पहुंचाएं और वहीं रुकें। जिस तरह विधानसभा चुनाव में आनंदाराव बोंडारकर को विजयी बनाया गया, उसी तरह महानगरपालिका चुनाव में भी शिवसेना पर विश्वास जताते हुए भगवा फहराएं और विकास का मार्ग प्रशस्त करें।

किया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुले तौर पर उस अपक्ष उम्मीदवार को समर्थन देते हुए उसे विजयी बनाने की अपील भी की थी। स्वयं शिवसेना के विधायक होते हुए पार्टी के ही उम्मीदवार के खिलाफ अपनाई गई इस भूमिका से स्थानीय शिवसैनिकों में तीव्र नाराज़गी देखने को मिली।

यह पूरा घटनाक्रम जब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विधायक कोहलीकर को मुंबई बुला लिया। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें मुंबई में रहकर पार्टी के प्रचार और संगठनात्मक कार्यों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नांदेड़ की स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप न करने की स्पष्ट हिदायत भी दी गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर की गई इस कार्रवाई से शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच यह स्पष्ट संदेश गया है कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नांदेड़ की सियासत में इस घटनाक्रम का अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आगामी चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।